



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2004/फाल्गुन 8, 1925

No. 214]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2004/PHALGUNA 8, 1925

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

का.आ. 271(अ).—केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) “संदाय चैनलों के कार्यक्रमों का पारेषण संबोध्य प्रणाली के माध्यम से” [जिसे इसमें इसके पश्चात् सशर्त अभिगमन प्रणाली (कैस) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है], परिकल्पित है;

और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अधिसूचना संख्यांक का0आ0 39(अ), तारीख 14 जनवरी, 2003 के द्वारा केबल आपरेटरों के लिए प्रत्येक संदाय चैनल के कार्यक्रमों को चेन्नई महानगर क्षेत्र, ग्रेटर मुम्बई के नगरपालिका क्षेत्र, कोलकाता महानगर क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 जनवरी, 2003 से छह मास के भीतर, कैस के माध्यम से प्रसारित करना बाध्यकारी बनाया गया था ;

और अधिसूचना संख्यांक का0आ0 792(अ), तारीख 10 जुलाई, 2003 के द्वारा कैस 1 सितंबर, 2003 से लागू किए जाने को आस्थगित कर दिया था ;

और अधिसूचना सं० का0आ0 1000(अ), तारीख 29 अगस्त, 2003 के द्वारा कैस के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में वापस ले लिया गया था ; और

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में कैस के वापस लिए जाने के विरोध में अनेक पक्षकार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय गए थे ;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 4 दिसंबर, 2003 के आदेश द्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसाण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1000(अ), तारीख 29 अगस्त, 2003 को अभिखंडित कर दिया है ;

और दिल्ली के केबल आपरेटरों ने 15 दिसंबर, 2003 से कैस को लागू करने का विनिश्चय किया था ;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2003 की सिविल रिट याचिका संख्यांक 8993 और 8994 में तारीख 26 दिसंबर, 2003 के अपने आदेश में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में सरकार द्वारा कैस के क्रियान्वयन को रोकने से इनकार कर दिया और तीन मास के पश्चात् स्थिति का पुनर्विलोकन करने का भी विनिश्चय किया ;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश में अन्य बातों के साथ यह विचार व्यक्त किया है “..... हम चाहते हैं कि तीन मास की इस अवधि में सभी कमियां, उपभोक्ताओं द्वारा वहन की गई कठिनाइयां, क्रियान्वयन का प्रभाव और समस्याएं, यदि कोई हों, जो क्रियान्वयन से उद्भूत हुई हो, निर्धारित की जा सकेंगी और उस संबंध में उपचारी उपाय किए जाएं ;

उन टिप्पणों के सारांश के निबंधनों के अनुसार, जो क्रियान्वयन की वांछा करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए हैं, कोई विनियामक निकाय हो । हम चाहेंगे कि प्रत्यर्थी आगामी सुनवाई की तारीख से पूर्व इस दिशा में की गई कार्रवाई से इस न्यायालय को अवगत कराए..... ।”

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 26 दिसंबर, 2003 के आदेश के अनुपालन में और कैस के क्रियान्वयन के कारण उद्भूत मुद्दों के समाधान हेतु भी केन्द्रीय सरकार ने 9 जनवरी, 2004 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की परिधि के भीतर “प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं” को अंतर्विष्ट किया तथा भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 45(अ), तारीख 9 जनवरी, 2004 के द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अतिरिक्त कृत्य सौंपे थे ;

और केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से मानक सन्नियमों और उनकी अवर्तिता, संदाय चैनलों की दरों का पुनरीक्षण, जिसमें अंतिम उपाय भी हैं, विनिर्दिष्ट करने का आग्रह किया है ;

और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से उन निबंधनों और शर्तों के संबंध में, जिन पर कैस उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा तथा संदाय चैनलों और अन्य चैनलों पर विज्ञापनों के लिए अधिकतम समय विनियमित करने के लिए पैरामीटरों के संबंध में सिफारिश करने का निवेदन भी किया गया था ;

और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं के हित से संबंधित, जिसके अंतर्गत संदाय चैनल की कीमत जारी करना और सेट टाप बाक्सों के उपापन के लिए शर्तें भी हैं, संबंधित विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कैस के आस्थगन या वापस करने के लिए केन्द्रीय सरकार से समय-समय पर संपर्क किया है ;

और कैस के क्रियान्वयन के दौरान, स्टैक धारकों अर्थात् प्रसारणकर्ताओं, बहु सेवा आपरेटरों और स्थानीय केबल आपरेटरों में उपभोक्ताओं के हित के साथ टकराते हुए गहरे मतभेद दिखाई दिए ;

और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए अतिरिक्त कृत्यों के परिणामस्वरूप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं द्वारा वहन की गई कठिनाईयों, कैस के क्रियान्वयन के प्रभाव और क्रियान्वयन के अनुक्रम के दौरान महसूस की गई समस्याओं का निर्धारण करने के लिए अनेक कदम उठाए थे । परामर्श प्रक्रिया के भाग रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विभिन्न स्टैकधारकों से लिखित रूप में और उनके साथ बैठकों के माध्यम से सुसंगत विषयों पर टिप्पणियां प्राप्त की थीं, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की चार राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों और टिप्पणियों की परीक्षा की और अन्य देशों की विनियामक पद्धतियों पर भी विचार किया । भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विस्तृत परामर्श पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है ;

और कैस के क्रियान्वयन से संबद्ध परामर्श की प्रक्रिया और विभिन्न मुद्दों की परीक्षा में कुछ और समय लगने की संभावना है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अंतिम उपाय के रूप में यह सिफारिश की है कि चार महानगरों में कैस के क्रियान्वयन की अधिसूचना को या तो रद्द कर दिया जाए या कम से कम तीन मास के लिए इसे आस्थगन में रखा जाए और माननीय दिल्ली उच्च

न्यायालय की 2003 की सिविल रिट सं. 8993 और 8994, तारीख 26 दिसंबर, 2003 के निदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए ;

और दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी अंतरिम सिफारिश में यह बताया है कि बड़ी संख्या में मुद्दों का, विशिष्टतया साधारण उपभोक्ताओं से संबंधित कैस के वास्तविक क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है ;

और यह भी देखा गया है कि अधिनियम की धारा 4क के उपबंध समान रूप से उस आधार पर क्रियान्वित नहीं किए गए हैं, जिसके कारण अवैधताएं हुई हैं ;

और माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 26 दिसंबर, 2003 के अपने आदेश में भी बल दिया है कि उपभोक्ता की शिकायतें, कैस प्रदाताओं द्वारा निपटायी जानी चाहिए ;

और यह सरकार के लिए आवश्यक हो गया है कि कैस के क्रियान्वयन के दौरान जो मुद्दे, विशिष्टतया उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित, उठे हैं उन्हें निपटारा जाए । ऐसी किसी कार्रवाई में संबद्ध राज्य सरकार से विस्तृत परामर्श अंतर्वलित होगा और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को इन मुद्दों की परीक्षा और उन पर अंतिम सिफारिश करने के लिए कुछ और अधिक समय की भी अपेक्षा की है ;

और केन्द्रीय सरकार का, सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की गई अंतरिम सिफारिशें भी हैं, यह विचार है कि कैस का क्रियान्वयन ऐसी रीति में होना चाहिए जो जनता के व्यापक हित और उपभोक्ताओं के रक्षोपायों के लिए हो जो दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति में तब तक संभव नहीं है जब तक कि ऊपर उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता है ;

और लोक हित में यह आवश्यक हो गया है कि कैस के क्रियान्वयन से संबद्ध सुसंगत अधिसूचनाओं को निलंबित कर दिया जाए और साथ ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और अन्य अभिकरणों के साथ सम्यक् परामर्श के पश्चात् नई तारीखों और क्षेत्रों को अधिसूचित करने के उद्देश्य से उनका पुनर्विलोकन किया जाए ; और

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 9 के साथ पठित धारा 4क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तारीख 14 जनवरी, 2003 की अधिसूचना के साथ पठित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना स० का०आ० 39(अ) तारीख 10 जुलाई, 2003 और का०आ० 792(अ), तारीख 10 जुलाई, 2003 की अधिसूचना के प्रवर्तन को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही जब तक कि ऐसी तारीख को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न किया जाए, निलंबित करती है।

[फा. सं. 9/2/03-बीपी एंड एल (पीटी.)]

यू. एस. भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2004

S.O. 271(E).—Whereas Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) (hereinafter referred to as the Act) envisages “transmission of programmes of a pay channel through an addressable system” [hereinafter referred to as Conditional Access System (CAS)];

AND WHEREAS the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, by notification number S.O. 39(E) dated the 14th January, 2003, made it obligatory for the cable operators to transmit programmes of every pay channel, through CAS in the Chennai Metropolitan area, Municipal Council of Greater Mumbai area, Kolkata Metropolitan area and the National Capital Territory of Delhi within six months from the 15th January, 2003;

AND WHEREAS by notification number S.O. 792(E) dated the 10th July, 2003, the implementation of CAS was deferred to the 1st September, 2003;

AND WHEREAS by notification number S.O. 1000(E) dated the 29th August, 2003, the implementation of CAS was withdrawn in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS a number of parties approached the Hon’ble High Court of Delhi, against the withdrawal of CAS in the National Capital Territory of Delhi;

AND WHEREAS the Hon’ble Delhi High Court in its Order dated the 4th December, 2003 quashed the notification of the

Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting number S. O. 1000 (E) dated the 29th August, 2003;

AND WHEREAS the Cable operators in Delhi decided to implement CAS from the 15th December, 2003;

AND WHEREAS the Hon'ble High Court of Delhi in the Civil Writ Petition number 8993 and 8994 of 2003 in its order dated the 26th December, 2003, declined to restrain the Government from implementing CAS in the National Capital Territory of Delhi and decided to review the situation after three months;

AND WHEREAS the Hon'ble High Court of Delhi observed in its aforesaid order, *inter alia*, that “.....we desire that in this period of three months all the loopholes, difficulties faced by the consumers, effect of the implementation and problems, if any, arising out of the implementation can be assessed and remedial measures be taken in that regard.

There has to be some regulatory body in terms of the synopsis of comments which have been filed by the respondent to see the implementation. We would like the respondent to enlighten this Court of the steps taken in this direction before the next date of hearing.....”;

AND WHEREAS in compliance of order dated the 26th December, 2003 of the Hon'ble Delhi High Court and also with a view to address the issues arising on account of implementation of CAS, the Central Government, brought “broadcasting services and cable services” within the ambit of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) on the 9th January, 2004 and entrusted the additional functions to the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) by the notification of the Government of India in the Ministry of Communication and Information Technology number S. O. 45 (E) dated the 9th January, 2004;

AND WHEREAS the Central Government has requested the TRAI to specify standard norms for, and periodicity of, revision of rates of pay channels, including interim measures;

AND WHEREAS the TRAI was also requested to make recommendations regarding the terms and conditions on which the CAS

shall be provided to customers and the parameters for regulating maximum time for advertisements in pay channels as well as other channels;

AND WHEREAS the State Governments of National Capital Territory of Delhi, Maharashtra, Tamilnadu and West Bengal have, from time to time, approached the Central Government for deferment or withdrawal of CAS citing various reasons relating to consumers' interest, including the issue of pricing of pay channels and terms and conditions for procurement of Set Top Boxes;

AND WHEREAS in the course of implementation of CAS, a deep divide has been noticed among the stakeholders, that is to say the broadcasters, multi-service operators and local cable operators, impinging on the consumers' interest;

AND WHEREAS consequent upon entrusting the additional functions to the TRAI, it initiated a number of steps to assess the difficulties faced by the consumers, the effect of the implementation of CAS and the problems faced during the course of implementation. As part of the consultation process, the TRAI obtained comments on relevant matters in writing as well as through its meetings with various stakeholders, examined the views or comments received from the four State Governments of Delhi, West Bengal, Maharashtra and Tamilnadu and also considered the regulatory practices in other countries. The TRAI is in the process of preparing a detailed Consultation Paper;

AND WHEREAS as the process of consultation and examination of various issues connected with the implementation of CAS is likely to take some more time, the TRAI, as an interim measure, has recommended that the implementation of CAS in the four metros be either denotified or kept in abeyance for at least three months and necessary action be taken keeping in view of the directions of the Hon'ble High Court of Delhi dated the 26th December, 2003 in the Civil Writ Petition number 8993 and 8994 of 2003;

Whereas it has been brought out by the TRAI in its Interim Recommendation that a large number of issues concerning particularly the general consumers need to be resolved for a meaningful implementation of CAS;

AND WHEREAS it has also been observed that the provisions of section 4A of the Act have not been uniformly implemented on ground, thereby resulting in illegalities;

AND WHEREAS the Hon'ble High Court, in its order dated the 26th December, 2003, has also stressed that the consumer grievances should be addressed by the providers of CAS;

AND WHEREAS it is essential for the Government to address the issues which have arisen during the course of implementation of CAS, particularly relating to the consumers' interest, such an exercise would involve detailed consultations with the concerned State Government and the TRAI requires some more time to examine these issues and make its final recommendations;

AND WHEREAS after careful consideration of all the relevant facts and circumstances, including the interim recommendations made by the TRAI, the Central Government is of the view that the implementation of CAS should be in a manner that is in the larger interest of the public and safeguards the interest of consumers, which unfortunately, in the present situation, is not possible unless the issues raised above are addressed;

AND WHEREAS it has now become necessary in the public interest to suspend the relevant notifications concerning implementation of CAS and simultaneously take a review, after due consultation with the TRAI and other agencies, with the objective of notifying fresh dates and areas; and

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4A, read with section 9 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government, having been satisfied that it is necessary in public interest so to do, hereby suspends the operation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting number S.O. 39(E) dated the 14th January, 2003 and S. O. 792(E) dated the 10th July, 2003 read with the notification dated 14th January, 2003 on and from the date of publication of this notification until such date as may be notified by the Central Government.

[F. No. 9/2/03-BP & L (Pt.)]

U. S. BHATIA, Jt. Secy.